

आजीविका हेतु सशक्तिकरण : राज्य नीति तथा
निजी क्षेत्र व नागर समाज के प्रयास हेतु
राज्य स्तरीय संगोष्ठी



अपवंचित समुदाय के
स्थायी जीवनयापन एवं
हकदारी के मुद्दों पर
विचार



दिनांक

22-23 सितम्बर, 2005

समय

प्रातः 9:30 से सायं 5:30

स्थान

गन्ना संस्थान, डालीबाग
लखनऊ

स्थाई आजीविका हेतु गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य पाने में साझेदारी

मानव विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अन्तराष्ट्रीय स्तर पर न्यू यार्क में दिगंत सितम्बर 2000 हुई बैठक में सहस्रत्राब्दी विकास लक्ष्यों (मिलेनियम डेवलपमेंट गोलस) का निर्धारण किया गया जिसमें भारत ने भी अपनी वचनबद्धता दी। इन लक्ष्यों को सरकारी, गैरसरकारी, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य कार्यदायी संस्थाओं ने स्वीकारा व अपने कार्यों में इनका निर्धारण किया। सभी का उद्देश्य मानव विकास हेतु गरीबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण इत्यादि से जुड़ी उपलब्धियों को सुनिश्चित करना है।

मिलेनियम डेवलपमेंट गोलस के अन्तर्गत भारत में विद्यमान सर्वव्यापी बेरोजगारी व उससे जुड़ी गरीबी एक अति चिन्ताजनक मुद्दा है जो सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारतवर्ष में विगत दशकों में गरीबी के स्तर में निरन्तर गिरावट आई है जिसके फलस्वरूप ही मानव विकास में भारत का सूचकांक 48 प्रतिशत हो पाया है (HDR 2003)। परन्तु अभी भी -

❖ 28 प्रतिशत भारतीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।

❖ करोड़ों लोगों को आवश्यक खाना भी नहीं मिल पा रहा है।

❖ लाखों लोग मकान, कपड़ा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं।

भारत सरकार की दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में निर्धारित लक्ष्य भी काफी हद तक संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास लक्ष्यों को प्रतिबिम्बित करते हैं।

सहस्रत्राब्दी विकास लक्ष्य

अत्याधिक गरीबी और भूख का उन्मूलन प्रति दिन एक डालर से भी कम कमाने वाले व्यक्तियों के अनुपात का आधा करना।

भूख के कारण व्यथित लोगों के अनुपात का आधा करना।

सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना

यह सुनिश्चित करना कि बालक एवं बालिका का समान रूप से पूरी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो।

लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना

शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक असमानता को दूर करना।

शिशु मृत्यु दर में कमी

पाँच वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर को दो तिहाई अनुपात तक कम करना।

मातृ स्वास्थ्य में सुधार

मातृ मृत्यु दर में तीन-चौथाई तक कमी लाना।

पैक्स कार्यक्रम

यह कार्यक्रम विकास के विभिन्न आयामों - समुदायों के संगठन व सशक्तिकरण, पंचायतों के सुदृढीकरण तथा निर्धन वंचित वर्गों व महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर पैरोकारी - पर केन्द्रित है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन लक्षित क्षेत्रों में नागर समाज संस्थाओं (Civil Society Organization-CSO) द्वारा किया जा रहा है। यह कार्यक्रम देश के 6 राज्यों - महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड व उत्तर प्रदेश - में चल रहा है। PACS कार्यक्रम का प्रबंधन Development Alternatives व Price Water House Cooper द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में पैक्स कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश PACS कार्यक्रम को शुरू करने में अग्रणी रहा है। वर्तमान में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 20 जिलों के 93 विकास खण्डों में 94 नागर समाज संगठनों के माध्यम से 36 परियोजनाओं का संचालन हो रहा है। रु 23.00 करोड़ की कुल लागत वाली इन परियोजनाओं के अंतर्गत प्रदेश की 1250 ग्राम पंचायतों के 2535 गांवों में

विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।

अतः इस ढांचे के अन्तर्गत **DFID** भारत सरकार की मदद कर रहा है। इस सहयोग हेतु एक योजना का निर्माण किया गया है जिसमें गरीबों की संख्या बढ़ाकर सशक्त करते हुये गरीबी रेखा से ऊपर करने की रणनीति पर कार्य किया जा रहा है जिसे निर्धनतम क्षेत्र नागर समाज (**PACS**) कार्यक्रम का नाम दिया गया है। पैक्स कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन का एकलौता सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो देश के 6 राज्यों (महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड एवं उत्तर प्रदेश) के अत्यन्त पिछड़े 108 जिलों में संचालित किया जा रहा है। पैक्स के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों की सीख, उपलब्धि एवं आई दिक्कतों को राज्य स्तर पर सरकार एवं कार्यदायी संस्थाओं के साथ सघन स्तर पर अनुभवों का आदान प्रदान कर आगे की स्पष्ट एवं सामुदायिक रणनीति निर्धारण हेतु राज्य स्तरीय संगोष्ठी दिनांक **22-24** सितम्बर, **2005** को लखनऊ में आयोजित की जा रही है।



पैक्स के अन्तर्गत विकास के मुद्दें

पैक्स कार्यक्रम इस तरह परिकल्पित किया गया है ताकि गरीबों को सशक्त बनाने और स्थानीय समुदायों की क्षमता विकसित करने की सर्वाधिक प्रभावकारी नीतियों को निर्धारित अर क्रियान्वित किया जा सके। विकास से जुड़ी प्रमुख समस्याओं के समाधान हेतु पैक्स कार्यक्रम एक समग्र दिशा इंगित करता है, जिनमें विकास के निम्नलिखित मुद्दे भी शामिल हैं –

- बेहतर स्थानीय स्वशासन
- महिला संशक्तीकरण
- सामाजिक सम्बद्धता
- नीतिगत पैरवी
- स्वसहायता

पैक्स कार्यक्रम अपने साझेदारों को प्रोत्साहित करता है कि वे इन मुद्दों को सम्बोधित करने के लिए समाकलित तरीके अपनाएं तथा अन्य नागरिक समाज संगठनों के गठबन्धनों के जरिए काम करें। यह कार्यक्रम नेटवर्कों और समूहों के गठनों को बढ़ावा देना चाहता है ताकि उपरोक्त महत्वपूर्ण मुद्दों पर सम्मिलित प्रयास किया जा सके।

पैक्स और नागर समाज

गरीबी कम करने के साझे लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारतीय नागरिक समाज के साथ योनाबद्ध तरीके से काम करना डी.एफ.आई.डी. की कार्यनीति है। भारत सरकार भी चाहती है कि गरीबी हटाने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका बढ़े। अतः नागरिक समाज संगठनों के साथ भी डी.एफ.आई.डी. की साझेदारी इन सब बातों का परिणाम है। नागरिक समाज के साझेदारी के द्वारा यह कार्यक्रम उन असंख्य गरीबों तक भी पहुँच सकेगा जो ऐसे इलाकों में नहीं रहते हैं, जहाँ गरीबों की पक्षधर राज्य सरकारों के सहयोग से डी.एफ.आई.डी. के कार्यक्रम पहले से ही चल रहे हैं। इन बातों के अलावा, देश के कई निर्धनतम इलाकों में सरकार अर बाजार की शक्तियों से अधिक प्रभावकारी पहुँच नागरिक समाज संगठनों की है।

संगोष्ठी के लक्ष्य

संगोष्ठी का मुख्य लक्ष्य निर्धनतम जिलों के मुददों के प्रति सरकार एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं को संवेदनशील करना है। साथ ही परियोजना से जुड़े अपवंचित समुदायों को अवगत कराना कि उनकी आवाज परियोजना तक ही सीमित न रहकर राज्य स्तरीय नीति तक भी जा रही है। साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान हेतु गम्भीर प्रयास भी किये जा रहे हैं।

आज आजीविका व हकदारी से जुड़े मुददों पर बातचीत एवं पहल करने के लिए सहज तथा साकारात्मक वातावरण की जरूरत है जिससे विभिन्न क्षेत्रों के हितगामियों को संगठित होकर काम कर सकें। इन प्रयासों से अपनी पहुँच का विस्तार किया जा सकता है तथा विकास की ओर उठाये गये कदमों का दूरगामी प्रभाव भी सुनिश्चित किया जा सकता है। यह कार्यशाला नागर समाज को सीखने के अवसर भी प्रदान करेंगे जिससे –

- नवीन एवं सफल तरीकों तथा अनुभवों की पहचान कर कार्यक्षेत्रों में किए गए विभिन्न हस्तक्षेपों को दोहराया जा सके।
- गरीबों के स्थाई जीवन यापन के साधनों तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु आपसी सूझबूझ से एक ढांचागत रूपरेखा तैयार हो सके।
- गरीबों के जीवन यापन में गुणात्मक सुधार एवं बेहतरी हेतु सरकारी नीतियों का आकलन करते हुये नीति क्षेत्र के प्रयासों, वित्तीय संसाधन एवं दाता संस्थाओं की नीतियों के अनुरूप सामंजस्य कर रणनीति का निर्धारण किया जाए।



साझा संकल्प

कार्यशाला के अंतिम दिन उत्तर प्रदेश सरकार, मीडिया, निजी क्षेत्र व PACS कार्यक्रम के मध्य, राज्य के विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक साझा संकल्प की घोषणा किया जाना प्रस्तावित है जिससे सभी की जिम्मेदारियों को सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही आनेवाले दिनों में प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाये जा सके। संगोष्ठी में पैक्स सहयोगी संस्थाओं के साथ साथ सरकारी, गैर-सरकारी संस्थाओं, वित्तीय सहयोगी संस्थाओं, मीडिया, दाता संस्थाओं तथा कार्पोरेट जगत के प्रतिनिधियों द्वारा सहभागिता की जायेगी।



आयोजक
बेटी फाउण्डेशन
सी-842, एच रोड,
महानगर,
लखनऊ - 226 006

मार्गदर्शन
समन्वय समिति



सहयोग-प्रबंधन सलाहकार
डेवेलपमेंट अल्टरनेटिव्स

प्राइस वाटर हाउस कूपरस् (प्रा०) लि०

111/9 -जेड, किशनगढ़, वसन्त कुंज, नई दिल्ली -110 070